



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 722]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 9, 2018/आश्विन 17, 1940

No. 722]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 9, 2018/ASVINA 17, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर, 2018

सं. 51/2018-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 1012(अ).—जहाँ कि निर्दिष्ट प्राधिकारी (एतश्मिन पश्चात जिसे प्राधिकारी से संदर्भित किया गया है) ने चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहाँ से निर्यातित और भारत में आयातित "डकटाइल आयरन पाइप्स", जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 7303 00 30 या 7303 00 90 के अंतर्गत आते हैं के मामले में अधिसूचना संख्या 15/1006/2012-डीजीएडी, दिनांक 04 सितम्बर, 2013, जिसे दिनांक 04 सितम्बर, 2013 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत अपने अंतिम निष्कर्षों में इस विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहाँ से निर्यातित विषयगत माल पर प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की थी;

और जहाँ कि निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर, केन्द्र सरकार ने, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 23/2013-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 10 अक्टूबर, 2013, जिसे सा.का.नि. 680 (अ), दिनांक 10 अक्टूबर, 2013, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत इस विषयगत माल पर दिनांक 10 अक्टूबर, 2013 से प्रतिपाटन शुल्क लगाया था;

और जहाँ कि मैसर्स इलैक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड, मैसर्स श्रीकलाहस्ती पाइप्स लिमिटेड (एसपीएल) और मैसर्स जिंदल साँ लिमिटेड (एतश्मिन पश्चात जिसे आवेदक से संदर्भित किया गया है) ने विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहाँ से निर्यातित विषयगत माल के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा करने और इसको जारी रखने के लिए उक्त प्राधिकारी के यहाँ आवेदन दिया है;

और जहाँ कि उक्त प्राधिकारी ने उक्त आवेदन पर विधिवत विचार किया है और आदेश फाइल संख्या 7/18/2018-डीजीएडी, दिनांक 17 मई, 2018 को जारी करके यह कहा है कि :

क) आवेदक ने इतना पर्याप्त और संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि उसके आधार पर सनसैट रिव्यू जांच शुरू की जा सके; और

ख) अतः सक्षम प्राधिकारी ने यह निर्णय लिया है कि चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित “डक्टाइल आयरन पाइप्स” के आयात के बारे में सनसैट रिव्यू जांच किए जाने के लिए यह मामला उपयुक्त नहीं है।

और जहाँ कि मैसर्स ज़िंदल साँ लिमिटेड (एतश्मिन पश्चात जिसे याचिकाकर्ता के रूप में संदर्भित किया गया है) ने माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष एक विशेष सिविल एप्लीकेशन संख्या 12368/2018 दायर किया था और माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 26 सितम्बर, 2018 के आदेश में कहा है कि:

“12. तदनुसार डीजीएडी का दिनांक 17.05.2018 का विवादित आदेश निरस्त किया जाता है क्योंकि यह युक्तिसंगत नहीं है। इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से 06 महीने के भीतर तथा कानून के अनुसार प्रतिवादी प्राधिकारी नए सिरे से सनसैट रिव्यू शुरू किए जाने के लिए आवेदन पर विचार करेगा। जब तक की ऐसा निर्णय नहीं ले लिया जाता है प्रतिपादन शुल्क, जो कि 09.10.2018 को और उसके बाद से समाप्त हो रहा है, को आगे जारी माना जाएगा। तदनुसार याचिका स्वीकार की जाती है। नियम निरपेक्ष बनाया जाता है। सीधे वितरण की अनुमति है।”

अतः अब, सीमा शुल्क टैरिफ (पाठित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपादन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 23 के साथ पठित, उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 26 सितम्बर, 2018 के माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 23/2013, सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 10 अक्टूबर, 2013, जिसे सा.का.नि. 680(अ), दिनांक 10 अक्टूबर, 2013 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात और स्पष्टीकरण से पहले निम्नलिखित पैराग्राफ को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“3. पैराग्राफ 2 में निहित किसी भी बात के बावजूद यह अधिसूचना 09 अप्रैल, 2019 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, लागू रहेगी, यदि इसके पहले इसको वापस नहीं ले लिया जाता है तो।”

[फा. सं. 354/3/2007-टीआरयू (पार्ट. I)]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 23/2013, सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 10 अक्टूबर, 2013 को सा.का.नि. 680(अ), दिनांक 10 अक्टूबर, 2013 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th October, 2018

No. 51/2018-Customs (ADD)

G.S.R. 1012(E).—Whereas in the matter of Ductile iron pipes (hereinafter referred to as the subject goods) falling under tariff items 7303 00 30 or 7303 00 90 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from China PR, (hereinafter referred to as the subject country), and imported into India, the designated authority (hereinafter referred to as authority) in its final findings *vide* notification number 15/1006/2012-DGAD dated the 4th September, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 4th September, 2013, had recommended continuation of anti-dumping duty on the imports of subject goods, originating in, or exported from the subject country;

And whereas, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, the Central Government had imposed anti-dumping duty on the subject goods with effect from the 10th October, 2013 *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 23/2013-

Customs (ADD) dated the 10th October, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 680 (E), dated the 10th October, 2013;

And whereas, M/s Electro Steel Casting Limited, M/s Srikalahasti Pipes Ltd. (SPL) and M/s Jindal Saw Limited (hereinafter referred as applicants) filed an application before the authority for review and continuation of the anti-dumping duties, imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

And, whereas the said application was examined by the authority and authority issued an Order F. No. 7/18/2018 - DGAD dated the 17th May, 2018 stating that:

- a) the applicant has not been able to provide sufficient and satisfactory evidence to initiate sunset review investigation; and
- b) therefore, the authority decides that the case is not fit for initiation of sunset review investigation concerning import of "Ductile Iron Pipes" originating in or exported from China PR.

And whereas, M/s Jindal Saw Limited (hereinafter referred as petitioner) filed a Special Civil Application No. 12368 of 2018 before the Hon'ble High Court of Gujrat and the Hon'ble High Court of Gujrat *vide* Judgement dated the 26th September, 2018, has ordered that:

"12. Accordingly, Impugned order dated 17.05.2018 of DGAD is set aside, as the same is without reasons. The respondent authority shall decide the application requesting a sunset review afresh, in accordance with law, within six months from the date of receipt of the order. Till such a decision is taken, the period of anti-dumping duty, which ceases to have effect on and from 09.10.2018, shall stand extended. Petition is allowed accordingly. Rule is made absolute. Direct service is permitted."

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the said Customs Tariff Act read with rules 18 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 and in pursuance of the Hon'ble High Court Judgement dated the 26th September, 2018, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 23/2013, Customs (ADD), dated the 10th October, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 680(E), dated the 10th October, 2013, namely:-

In the said notification, after paragraph 2 and before the Explanation, the following paragraph shall be inserted, namely: -

"3. Notwithstanding anything contained in paragraph 2, this notification, unless revoked earlier, shall remain in force up to and inclusive of the 9th April, 2019."

[F. No. 354/3/2007-TRU (Pt. I)]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

Note : The principal notification No. 23/2013- Customs (ADD), dated the 10th October, 2013 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 680(E), dated the 10th October, 2013.